



'मोदी का उत्तराधिकारी ढूँढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं, वे 2029 में भी प्र.मंत्री के उच्चतम पद पर रहेंगे'

महाराष्ट्र के मु.मंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने स्पष्ट शब्दों में पत्रकारों से कहा। जैसा कि विदित ही है फड़नवीस को मोदी

के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है

-डॉ. सतीश मिश्र-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-
नई दिल्ली, 31 मार्च महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस, जिनके सत्तासीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी होने के संभावना बढ़ती जा रही है, ने आज कहा कि देश के कार्यपालिका प्रधान के उत्तराधिकारी को "तलाश की कोई जरूरत नहीं" है। मोदी 2029 में देश के इस शोर्पे को पुनः संभालेंगे।

उनका यह बयान शिव सेना (यूनिटी) संसद संघरश उत्तर के इस दावे के जवाब में आया है कि आरएसएस मोदी के उत्तराधिकारी को तलाश में है। आज सुबह गत रोज़ ने कहा था कि एक बार भागवत को यह संदेश देना था कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुये, फड़नवीस ने कहा, "उनके

- दूसरी ओर शिव सेना (यूनिटी) के वरिष्ठ नेता संजय रात, दिन भर बयान देते रहे कि, मोदी नागपुर, आरएसएस के मुख्यालय संघ को बताने गये थे कि वे इस्तीफा देने जा रहे हैं तथा रात के अनुसार, नया प्र.मंत्री महाराष्ट्र का बासिंदा होगा।
- फड़नवीस ने रात की दोनों बातों का खण्डन किया और कहा, भारतीय संस्कृत में बाप के जीते जी उसके उत्तराधिकारी की बात करना बेहूदापन माना जाता है। यह मुगल कल्चर जरूर हो सकता है।
- संघ के वरिष्ठ नेता, सुरेश भैयाजी जोशी, ने इस मुद्दे पर आगे कहा, "उनकी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं आई कि मोदी के उत्तराधिकारी के चयन पर कहीं भी चर्चा ढूँढ़ी जाएगी।"
- भैयाजी ने यह भी कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि 75 की उम्र पर करने वाले कोई पद नहीं पा सकते सरकार में। वर्तमान में ही अस्सी वर्षीय, बिहार के नेता, जीतन राम माझी के नन्दीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं।

(मोदी) उत्तराधिकारी की तलाश की कोई जारी रहत नहीं है। ये हमारे नेता हैं और बने रहेंगे।" वर्तमान विवाद की जड़ स्वयं मोदी में ही निहित है। उन्होंने 2014 में सत्ता में आपे पर नीति प्रतिपादित की थी कि 75 वर्ष से अधिक उम्र पर नेता सरकार का विस्तार नहीं रहेंगे तथा पार्टी में भी पार्दिवारी नहीं रहेंगे। इस नीति के फलवरूप, एल.के.आडवाणी, डॉ. मुरली मोहन जोशी, यशवंत सिंह तथा अरुण शौरी जोशी नेता सेवानिवृत्त श्रेणी में आगे थे। दरअसल, अटल विहारी जावेयी, जो उस समय जीवित थे, आडवाणी तथा जोशी के साथ ही, अप्रभावी तथा दायित्व-पूर्त कर दिये गये थे। उनके नाम प्रदर्शन नेताओं को मिलते हैं। वर्तमान विवाद की तलाश कोई बैठक हुई और न भाजपा सरकार ने इससे उप्रदान लोगों को दीर्घ अंतिम पृष्ठ पर।

रविवार व अन्य पेड़ लीव सेवा अवधि में शामिल मानी जाए

जयपुर, 31 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के उत्तराधिकारी को खारिज कर दिया है, जिसमें न्यायाधिकरण ने कर्मचारी की माननी करते समय रवाणा और अन्य संवैतनिक अवकाशों को घान में नहीं रखा था। इसके साथ ही, अदालत ने प्रकरण को नए सिरे से सुनवाई के लिए एक नन्दीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबूक बन जाती हैं। -शेक्सपियर

लोकतंत्र में आलोचना

अपराध नहीं है

S

रकरों से सामान्यत्व आलोचना को सहन नहीं कर पाती और कई बार आलोचकों के लिए रुद्ध राष्ट्रदूत की कार्रवाही तक प्रारंभ कर देती है। पुलिस भी उनके इस कान में पूरी सहायता करती है। यह दुर्दायी ही है कि उत्पीड़क, जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संविधान और कानून के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा है, वह भी सत्ता धरी दर्श करते हैं। इन्होंने कानूनों का शासन था, तो स्वतंत्रा का एवं अपराध करने का लिए तपत जाती है।

देश में समय-समय पर लेखक, साहित्यकार, कवि, व्यंगकार एवं अन्य सुजन कर्मी हुए हैं, जिन्होंने अनीं कानों का सामान्य से सामान्यत्व आलोचना को लिया और जनता को जागृत करने का कार्य भी किया। बज अंग्रेजों का शासन था, तो स्वतंत्रा का एवं अपराध करने की अपेक्षा है। यह दुर्दायी ही है कि उत्पीड़क, जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संविधान और कानून के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा है, वह भी सत्ता धरी दर्श करते हैं।

गत चार वर्षों से ऐसा लगता है कि विभिन्न सरकारों की उड़ान, आलोचना के बढ़ी महत्वपूर्ण घटनाकाल होती जा रही है। समय-समय पर, विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिये जाने के बावजूद भी कि, भारतीय संविधान नागरिकों को अधिकारित की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सरकारें ऐसे आलोचकों को प्रताड़ित करने में लगे रहती हैं। इसके दो उदाहरण हाल ही में सामने आए हैं। पहला, कांग्रेस के राजसभा संसद के अलंकार व्यक्ति के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का, है, जो सांसद होने के साथ-साथ अच्छे शायदी भी है।

29 दिसंबर, 2024 को जामनगर, गुजरात में इमरान प्रतापगढ़ी, जामनगर नगर परिषद के सदस्य अल्लाफ़ गफकार भाई खाली के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक सामाजिक विवाह समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो पृथग्मूले में एक गोत बज रहा था जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे:-

"ए खान के व्यासों बाट सुना,

गर कह की लाइड जुम्स से है

हम जुलूम से निमा देंगे

गर शम ए गरिया आतश है,

हर राह वो शमा जला देंगे।

गर लाश खानी अनीं की,

खतरा है तुम्हारी मसनद का,

उस खां की कासम, हम हंसते हैं, हंसते

उनकी लाशें दफना देंगे।

ए खान के व्यासों बाट सुनो....!"

इस गीत का इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने..... अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इसे समाज के विभिन्न वर्गों में फैलाने और आपने भी भिन्नों वाला ठहराये हुए, इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता की थी 1946, 1979, 299,300 के अंतर्गत एक आई आर आर कानून कर दिया गया। इस एक आई आर को निरस्त करने के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में अपील बनायी थी, किंतु न्यायालय ने एक आई आर निरस्त करने से इनकार कर दिया। इसके विरुद्ध उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयी अध्यक्ष ओंकार और न्यायालयी अध्यक्ष की खबरोंता को महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के निरस्त हुए, इमरान प्रतापगढ़ी को द्वारा, अधिकारित की खबरोंता को अपील बनायी थी, किंतु न्यायालय ने एक आई आर निरस्त करने से इनकार कर दिया।

इसी कानूनी विवाह के बावजूद भारतीय अध्यक्ष ओंकार और न्यायालयी अध्यक्ष की खबरोंता को अपील बनायी थी, किंतु न्यायालय ने एक आई आर निरस्त करने से इनकार कर दिया।

मानवीय उच्चतम न्यायालय ने नागरिक के विचारों और अधिकारित की खबरोंता की स्वतंत्रता की अहम मानते हुए यह कहा कि उक्त की खबरोंता का दायित्व न्यायालयी महिला भारतीय नागरिक वर्गों में फैलाने और आपने भिन्नों वाला ठहराये हुए, इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध भारतीय नागरिक अधिकार के निरस्त हुए, इमरान प्रतापगढ़ी को द्वारा, अधिकारित एक आई आर आर कानून कर दिया गया। इस 64 पृष्ठों के निर्णय में हम स्पष्ट कर दिया है कि भारत का गणतंत्र 75 सालों बाट इनका कमज़ोर नहीं है कि किसी की खबिता, लेख, व्यंग या स्टैंड के अपील कोर्ट की अधिकारीय अधिकारी से उसे खतरा उत्पन्न हो जाय।

मानवीय उच्चतम न्यायालय के न्यायालयी अध्यक्ष ओंकार और न्यायालयी अध्यक्ष की खबरोंता के बावजूद भारतीय अधिकारित की खबरोंता को महत्वपूर्ण भारतीय नागरिक वर्गों में फैलाने और आपने भिन्नों वाला ठहराये हुए, इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध भारतीय नागरिक अधिकार के निरस्त हुए, इमरान प्रतापगढ़ी को द्वारा, अधिकारित एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण प्रक्रिया तब सामने आया जो प्रतिशुद्ध स्टैंडअप कार्मेंडिंग के बावजूद भारतीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आर आर कानून कर दिया गया।

अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकारीय अधिकारित की खबरोंता के लिए गुरुतत उच्च न्यायालय में एक आई आ

